

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 24 जुलाई, 2007

**विषय:-** राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में नेहरू कालोनी तेगबहादुर रोड जंक्शन से रिंग रोड तक रिस्पना नदी पर सेतु सहित मार्ग का निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्य के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0-203/111-02-06-09(प्रा.आ.)/05 दिनांक 28 जनवरी, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में उपरोक्त कार्य की रू0 809.85 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 5.00 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा श्रमिक दरो में वृद्धि एवं सेतु के विस्तृत डिजाइन में परिवर्तन होने, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त पाईल फाउन्डेशन के स्थान पर पैल फाउन्डेशन का निर्माण एवं पूर्व में सेतु निर्माण के दौरान Clay Soil मिलने के कारण नींव की गहराई में वृद्धि होने आदि कारणों का उल्लेख करते हुए संशोधित अनुपूरक आगणन लागत रू0 178.18 लाख उपलब्ध कराया गया है जिस पर टीएसी दिल्ही द्वारा परीक्षणपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 163.90 लाख (एक करोड़ त्रैतस लाख नब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए सेतु निर्माण हेतु शासनादेश सं0-203/111-2-06-09(प्रा.आ.)/05 दिनांक 28 जनवरी, 2006 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृत धनराशि रू0 809.40 लाख को सम्मिलित करते हुए रुपये 809.40+ रू0 163.90 = रू0 773.75 लाख (रू0 सात करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि पुनरीक्षित लागत में इस कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए पुनः कोई भी अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। तथा इस हेतु मुख्य अभियन्ता के साथ-2 संबंधित अभियन्ताओं को पूर्ण रूप से दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय हेतु दी गई धनराशि रू0 0.10 लाख एवं रू0 5.00 लाख कुल रू0 5.10 लाख की स्वीकृति में उक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 768.65 लाख की धनराशि की व्यय की स्वीकृति धालू निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार घटान किया जायेगा।

4. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम दरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

5. आगणन में 25 प्रतिशत ओवर हेड चार्ज लिया गया है इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि 25 प्रतिशत में जो 15 मर्दे ली गई है। उनका मदवार क्या प्रतिशत निर्धारित है। अतः इसको सर्वप्रथम एम.ओ.आर.टी.एच. से प्राप्त कर लें तथा उसी के अनुरूप विस्तृत आगणन में प्राविधान कर लिया जाय। जिन मदों में ओवर हेड चार्ज देय

2) 2.1 111-2/07-09

कमल 2-

नियमानुसार मान्य नहीं है, उसके अवयव कम करते हुए इसमें संभावित बचत की सूचना से शासन को अवगत कराया जायेगा। कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए आगणन में प्राविधानित समस्त कार्य एम.ओ.एस.आर. टी. एण्ड एच. एवं लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्ट्यों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करना होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूमिस्वेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. समस्त सीमेन्ट की स्ट्रैलिंग को जाँच करने पर पंजिका में इंगित की जायेगी इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित सहायक अभियन्ता का होगा।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को कय कराने से पूर्व स्टोर चर्जेज नियमों का पालन करने का साथ-2 नियमानुसार विधिवत निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा इसकी पुष्टि स्थल साईट बुक में भी इंगित कराया जाना समीचीन होगा। उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. आगामी किस्त राब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. कार्य को समयबद्ध करते हुए मुख्य अभियन्ता स्तर-1 एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पुनः का समय-2 पर स्थल निरीक्षण करते हुए प्रत्येक 15 दिन के भीतर कार्य की प्रगति आख्या से शासन को अवगत कराया जायेगा।

14. उक्त योजना पर व्यय संगत मद में (मार्ग के चालू कार्य) के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही किया जाये।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.164/XXVII(2)/07, दिनांक 19 जून 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

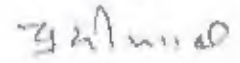
(अरविन्द सिंह हयाकी)  
अपर सचिव

संख्या- 1679  
(1)/111-2/07 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), आबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नदी वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून ।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गाड़ें बुक ।

आज्ञा से



(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव